भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

आतारांकित प्रश्न सं. 2818

बुधवार, दिनांक 05 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

मध्य प्रदेश में पीएम-कुसुम

2818. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में विशेषकर रतलाम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के अंतर्गत कृषि फीडरों के सौरकरण, सौर सिंचाई पंपों की स्थापना और विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत और स्थापित सौर पंपों, सौर ऊर्जा युक्त कृषि फीडरों का ब्यौरा क्या है और पीएम-कुसुम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में जिला-वार और विशेष रूप से उक्त निर्वाचन क्षेत्र में लाभान्वित किसानों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या पीएम-कुसुम के परिणामस्वरूप सिंचाई की लागत में कमी आई है, किसानों की आय में वृद्धि हुई है, बिजली की निर्बाध उपलब्धता हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा, शेष पात्र किसानों को पीएम-कुसुम का लाभ प्रदान करने, कृषि क्षेत्र में विद्युत राजसहायता के बोझ को कम करने और हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख) पीएम कुसुम एक मांग संचालित योजना है तथा मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। योजना का कार्यान्वयन राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) की जिम्मेदारी है। एसआईए द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में प्रगति इस प्रकार है:

(दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार)

पीएम कुसुम घटक	स्वीकृत	स्थापना
क (मेगावाट में)	1,401	201.66
ख (पंपों की संख्या)	59,400	24,682
ग (पंपों की संख्या)	1,75,000	62,378

रतलाम लोक सभा क्षेत्र, के अंतर्गत जिला-वार, प्रगति इस प्रकार है:

जिला	घटक क के अंतर्गत स्थापना (MW)	घटक क के अंतर्गत स्थापना (पंपों की संख्या)
रतलाम	7	981
झाबुआ	शून्य	67
अलीराजपुर	1	41

योजना में घटक ख के अंतर्गत किसी स्थापना की सूचना नहीं दी गई है।

(ग) राज्यों ने विद्युत की खरीद की कम हुई लागत, ऊर्जा की प्रति यूनिट आपूर्ति लागत में कमी, ऊर्जा हानि में कमी तथा अपने ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार की सूचना दी है।

मध्य प्रदेश की एसआईए ने पीएम कुसुम परियोजनाओं के माध्य में 2.94-3.25 प्रति यूनिट की कम टैरिफ की विद्युत खरीद की सूचना दी है।

घटक ख के अंतर्गत, राज्य 30% केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त 60% राज्य का हिस्सा भी प्रदान कर रहा है, जिससे किसानों के लिए सौर पंप की स्थापना सुलभ हो रही है।

(घ) पीएम कुसुम योजना को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और शेष पात्र किसानों को लाभ देने के लिए, मंत्रालय योजना के तहत नियमित जागरूकता, क्षमता-निर्माण और हितधारक संपर्क गतिविधियां चलाता है। इनमें क्षेत्रीय कार्यशालाएं, राज्यों के साथ समीक्षा बैठकें, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, प्रिंट, टेलीविजन और रेडियो आउटरीच अभियान और समय पर कार्यान्वयन और अधिक लाभार्थी भागीदारी की सुविधा के लिए राज्यों और डिस्कॉम के साथ योजना कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी शामिल है।

****